जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 43 संख्याः 103 प्रभात बीकानेर, सोमवार 8 नवम्बर, 2021 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रू.

विश्व में कितनी वैंडल सील हैं? सच्चाई यह है कि वैज्ञानिकों को अब तक पता ही नहीं था। अब ''साईन्स एडवांसेज़'' के सितम्बर 2021 के संस्करण में इस एन्टार्कटिक सील की वैश्विक आबादी का पहला आकलन छपा है, जिसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। शोध की मुख्य लेखक और युनिवर्सिटी ऑफ मिनसोटा की रिसर्च एसोसिएट मिशैल लरु ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि सील की संख्या हमारी उम्मीद से बहुत कम है। हमारे आकलन के हिसाब से विश्व में सिर्फ दो लाख मादा सील ही हैं। धरती के सूदूर दक्षिणी छोर, जहां शायद ही कोई अन्य स्तनपायी रहता हो, में बसेरा करने वाली ये सील दक्षिणी सागर के इकोसिस्टम में भी अहम् भूमिका निभाती हैं। एन्टार्कटिका को घेरे हुए इस सागर को विश्व का पांचवा महासागर मान लिया गया है।'' लरु ने बताया कि, दो प्रमुख कारणों से वैंडल सील दक्षिण सागर के लिए प्रमुख ''इण्डीकेटर'' प्रजाति हैं, एक तो यह कि, ये एन्टार्कटिका की ''फास्ट आइस'' (ऐसी बर्फ जो एन्टार्कटिका महाद्वीप से स्थायी रुप से सटी हुई है) पर रहना पसंद करती हैं, इस प्रकार सील और उसके आवास व व्यवहार को समझकर वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि जलवायु परिवर्तन से यह इकोसिस्टम किस प्रकार बदल रहा है। दूसरा कारण यह कि, वैंडल सील एन्टार्कटिक टूथफिश को खाती हैं। इस फिश को चिलिअन सी बास भी कहते हैं। लरु ने कहा कि ''ना केवल ये हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी देती हैं बल्कि, यह भी कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। क्योंकि एन्टार्कटिक टूथफिश एन्टार्कटिका के इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण भाग हैं। वैंडल सील का हालांकि बहुत अध्ययन हुआ है पर अभी तक इनकी सही संख्या पता नहीं थी, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास सही तकनीक नहीं थी। लरु ने कहा, ''एक -एक सील को देख सकने वाली सैटलाइट इमेजरी दस साल पहले उपलब्ध नहीं थी। पूर्व में उनकी गणना जलयानों व हवाई जहाज से की जाती थी। इसके आधार पर उनकी आबादी का अनुमान काफी ऊंचा, लगभग 8 लाख था। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं है कि सील की संपूर्ण आबादी वास्तव में घटी है। अब इस नए व ज्यादा सटीक आंकड़े से शोधकर्ताओं को भविष्य में आबादी की घटत-बढ़त को नापने में मदद मिल सकती है। वर्तमान में वैंडल सील आई.यू.सी.एन. की रैड लिस्ट में ''लीस्ट कंसर्न'' (कम चिंताजनक स्थिति) वाले वर्ग में हैं लेकिन उनकी आबादी का रुझान, संख्या घट रही है या बढ़ रही है, अज्ञात थी। लरु ने बताया कि यह नई सटीक गणना सैटलाइट तकनीक और सैंकड़ों हजारों सिटिज़न साइन्टिस्ट की वजह से संभव हुई है। लरु ने कहा ''सफेद बर्फ पर सील काले ब्लॉब की तरह दिखती हैं। सैटलाइट छवियों को जब कम्प्यूटर पर देखते हैं तो ये आराम से नज़र आ जाती हैं।''

'भाजपा बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ संघर्ष और तेज करेगी'

भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का मुद्दा मुख्यतः छाया रहा साथ ही पांच राज्यों में चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई

- **बैठक के दौरान जे.पी. नड्डा ने कहा कि, प. बंगाल में ममता बनर्जी के जाने और लोकतंत्र की वापसी तक भाजपा का संघर्ष पूरी कड़ाई से जारी रहेगा।**

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ परिसर से जुड़े। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ सहित आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह भी शामिल हुए।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा सहित भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों ने पार्टी व विभिन्न राज्यों में संगठन की मजबूती को लेकर मंत्रणा की। साथ ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में हुए विकास और उपलिब्धयों को आम जनता तक पहुंचाने की बात कही गई। बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक खत्म होने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने की बात कही है।

इस बैठक में छत्तीसगढ़ भाजपा कार्यालय से प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर, पूर्व मंत्री लता उसेंडी सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की कमियों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। सरकार की वादा-खिलाफी से उन्हें अवगत कराएंगे। सत्ता पाने के लिए गंगाजल लेकर कसमें खाने वाली सरकार अब अपने वादों से मुकर रही है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की भर्त्सना करते हुए कहा है कि वह राज्य की जनता के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी और राज्य में राजनीति की एक नयी इबारत लिखेगी। भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने रविवार को नयी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के प्रथम सत्र में पश्चिम बंगाल में पार्टी के बढ़ते जनाधार का उल्लेख करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में जब भी बंगाल में चुनाव होगा तब भाजपा प्रजातांत्रिक तरीके से बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल में प्रजातंत्र को, संविधान को बहाल करने के लिए लड़ेगी।

प्रथम सत्र की कार्रवाई की जानकारी केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने संवाददाताओं को दी। बाद में वित्त मंत्री ने बैठक में पारित राजनीतिक प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी कार्यकारिणी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और विपक्ष की नकारात्मक राजनीति की निंदा की है।

नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, ''पश्चिम बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया है।'' उन्होंने कहा कि विधान सभा चुनावों के बाद वहां भाजपा के कई कार्यकताओं की हत्या कर दी गयी है पर ''भाजपा पश्चिम बंगाल की जनता के साथ डटी रहेगी।'' नड्डा ने पश्चिम बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाया है कि पार्टी प्रदेश में राजनीति की एक नयी कहानी लिखेगी। गौरतलब है कि भाजपा ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव बड़ी मेहनत और दमखम से लड़ा था और उसका दावा था कि इस बार चुनाव में नया खेला होगा और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार पलट जाएगी। पार्टी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी पर आज वह विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। लेकिन राज्य में राजनीतिक हिंसा के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो जैसे भाजपा के कुछ सांसद, विधायक और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए है।

महंगाई और पैट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ कांग्रेस के जन जागरण अभियान पर लगेगा ग्रहण

क्योंकि केंद्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पड़ोसी राज्यों में भी राजस्थान के मुकाबले 15 रुपए तक सस्ता मिल रहा है पैट्रोल-डीजल

- **राज्य में वैट कम करने के बजाय मुख्यमंत्री ने फिर लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र, एक्साइज ड्यूटी घटाने और जी.एस.टी. पुनर्भरण की मांग की।**

जयपुर, 7 नवम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस की ओर से 14 नवम्बर से आसमान छूती मंहगाई, पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस सहित आवश्यकता की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के विरूद्ध प्रदेशभर में होने वाले जागरूकता जन सम्पर्क कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ही लोगों के निशाने पर आती दिख रही है। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 और पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है। वहीं कई प्रदेशों ने अपने स्तर पर वैट में कमी की है और जनता को राहत मिली है। दूसरी और पड़ोसी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में इस समय सबसे महंगा डीजल-पेट्रोल मिल रहा है।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट रूप से वेट कम करने से मना कर दिया है। ऐसे में अब प्रदेश कांग्रेस दुविधा में है कि आखिरकार वह बढ़ती महंगाई को लेकर कैसे 14 नवंबर से जनता के बीच जन जागरण कर पाएगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की दुविधा यही नहीं है कि केंद्र सरकार ने डीजल पर 10 और पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहां पहले से ही राजस्थान के मुकाबले 10 से 12 रुपए पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम हैं। वहां भी राज्य सरकारों ने वेट कम कर दिया है और रविवार को कांग्रेस शासित राजस्थान के पड़ोसी राज्य पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पेट्रोल और डीजल पर क्रमश 10 और 5 रुपए कम कर दिए हैं। ऐसा होने का असर ना सिर्फ आम जनता पर पड़ रहा है बल्कि पड़ोसी राज्यों के नजदीकी जिलों के पेट्रोल-डीजल डीलरों पर भी पड़ रहा है। उन जिलों के वाहन चालक पड़ोसी राज्यों से जाकर पेट्रोल-डीजल भरवा रहे हैं। इससे डीलरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं राज्य सरकार को भी मिलने वाला कर नहीं मिल पा रहा है।

अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी दबाव है कि वह स्टेट वेट कम करे लेकिन ऐसा करने के बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पेट्रोल-डीजल पर लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी में और कमी करने का आग्रह किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जीएसटी पुनर्भरण के बकाया चल रहे 5,963 करोड़ रुपये का भुगतान जल्द करने का भी आग्रह किया है। रविवार को गहलोत ने अपने पत्र में यह भी दिखा कि यदि केंद्र सरकार ऐसा करती है तो महंगाई से जूझ रही जनता को राहत मिल पाएगी। पत्र में लिखा कि केन्द्र की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का वैट आनुपातिक रूप से अपने आप ही कम हो जाता है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केन्द्र सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्य में वैट की दर में पेट्रोल पर 1.8 रुपये प्रति लीटर व डीजल पर 26 रुपये प्रति लीटर की कमी स्वत: हो गई है। इससे राज्य के वैट राजस्व में लगभग 1800 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की हानि होगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए हमारी सरकार ने इस वर्ष की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

देवबंद में राजनेताओं के आने पर रोक

देवबंद (सहारनपुर) 7 नवम्बर (वार्ता)। सेकुलर दलों के नेताओं के देवबंद स्थित विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्था दारूल उलूम देवबंद में किसी न किसी बहाने आने के इरादो को

- **सेकुलर दलों के नेताओं के देवबंद स्थित विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्था दारूल उलूम देवबंद में किसी न किसी बहाने आने के इरादो को दारूल उलूम ने बडा झटका देते हुए चुनावों के दौरान उनके यहां आने पर रोक लगा दी है।**

दारूल उलूम ने बडा झटका देते हुए चुनावों के दौरान उनके यहां आने पर रोक लगा दी है।

दारूल उलूम देवबंद के चांसलर मुफ्ति अबुल कासिम नोमानी ने कहा कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश की आठ करोड़ जनता को लूटने का क्रम जारी रखना चाहती है लुटेरी गहलोत सरकार : देवनानी

'पैट्रोल-डीजल की कीमतें कम करने का प्रदर्शन करना मात्र कांग्रेस की नौटंकी'

- **'राज्य सरकार ने पैट्रोल-डीजल पर वैट कम नहीं किया तो सड़क से सदन तक घेरेगी भाजपा'।**

जयपुर/जोधपुर, 7 नवम्बर (का.प्र.)। भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर संगठन प्रभारी एवं पूर्व मंत्री अजमेर विधायक वासुदेव देवनानी ने पेट्रोल डीजल पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरा और कहा कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर पांच रुपए और दस रुपए घटाकर आमजन को राहत प्रदान की है लेकिन मुख्यमंत्री वैट कम करने को राजी नहीं है, कोविड के समय राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से करीब दस हजार रुपए की खुली लूट जारी रखी थी। केन्द्र की मोदी सरकार ने कीमतें कम करके जनता को राहत प्रदान की है। केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद भाजपा शासित अधिकांश राज्यों ने आदेश का अनुसरण करते हुए वेट कम किया लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार को अपना 1800 करोड़ का हिस्सा कम होने की चिंता सता रही है। गहलोत सरकार प्रदेश की आठ करोड़ जनता को राहत नहीं देना चाहती और प्रदेश की जनता को लूटने का क्रम जारी रखना चाहती है। जबकि यही लोग केन्द्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे अब राज्य सरकार वेट कम क्यों नहीं कर रही। पेट्रोज-डीजल की कीमतें कम करने का प्रदर्शन करना मात्र कांग्रेस की नौटंकी ही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का बस एक ही काम रह गया है मोदी, भाजपा और आरएसएस को कोसना और मिथ्या आरोप लगाना। येन-केन प्रकारेण मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। इसी के चलते पिछले पौने दो वर्ष से अपने घर जोधपुर तक को नहीं संभाला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गहलोत का राज्य के विकास को लेकर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनको आभास हो चुका है कि भविष्य में वो तो सत्ता में नहीं आने वाले।

देवनानी ने रविवार को यहां जोधपुर प्रवास के दौरान मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि दुखी है। किसी को थाने में धरना देना पड़ रहा है तो कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। गहलोत सरकार ने प्रदेश को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय नौका पर पाकिस्तान ने फायरिंग की

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। पाकिस्तानी नौसेना ने रविवार को गुजरात तट पर स्थित एक भारतीय नाव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे की दर्दनाक मौत हो गई है और एक मछुआरा घायल हो गया। मृतक मछुआरे का नाम श्रीधर बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया वहीं, घायल

- **पाकिस्तानी नौसेना की ओर से की गई इस फायरिंग में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई व एक अन्य घायल हो गया।**

को द्वारका के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी नौसेना ने इस तरह की हरकत की है। इससे पहले भी पाक की तरफ से कई मछुआरे की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। पिछले साल अप्रैल में भी पाकिस्तानी नौसेना ने दो नावों पर फायरिंग कर दी थी।

जी-20 के रोम घोषणापत्र में भारत का दबदबा कायम हुआ

घोषणापत्र में भारत के सुझाये नौ मुद्दों को प्रमुखता से शामिल किया गया

- **प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 बैठक के दौरान कई बार करोना की विभीषिका को देखते हुए डब्ल्यु.एच.ओ. की तरफ से दूसरे देशों के टीकाकरण को मंजूदी देने की अपील की थी। इस विषय को भी जी-20 की घोषणापत्र में जगह दी गई और इसके तीसरे दिन ही डब्ल्यु.एच.ओ. ने भारत को स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी।**
- **जी-20 इस घोषणापत्र के बाद भारत तेजी से दूसरे देशों के साथ हवाई मार्ग व पर्यटन को खोलने का समझौता कर सकता है।**
- **कोयला बिजली संयत्रों को लेकर भी विश्व समुदाय ने भारत की मांग को स्वीकार किया है। विकसित देशों का दबाव था कि सभी ताप बिजली संयत्रों को बंद करने का लक्ष्य तय होगा। लेकिन भारत का कहना था कि, पहले चरण में ताप बिजली संयंत्रों को किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं देने की शुरुआत होनी चाहिए।**

नई दिल्ली, 7 नवम्बर। दुनिया में आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे मजबूत 20 देशों के संगठन जी-20 की बैठक समाप्त हो चुकी है। बीते रविवार को इसकी तरफ से जारी घोषणा पत्र को विश्व की मौजूदा कई चुनौतियों के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। इस घोषणा पत्र में कम से कम नौ ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी भारत लंबे समय से मजबूती के साथ पैरोकारी करता रहा है, जिसमें पूरी दुनिया में कारपोरेट टैक्स की न्यूनतम दर 15 प्रतिशत करना प्रमुख है।

सूत्रों का कहना है कि घोषणा पत्र में शामिल कई मुद्दे हैं जिसको लेकर पीएम नरेन्द्र मोदी ने समूह के देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग-अलग मुलाकात में उठाया था। पी.एम. मोदी ने कई बार करोना की विभीषिका को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू.एच.ओ.) की तरफ से दूसरे देशों के टीकाकरण को मंजूरी देने की अपील की थी। इसको जी-20 की घोषणा पत्र में जगह दी गई और इसके तीसरे दिन ही डब्ल्यू.एच.ओ. ने भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है।

भारत का मानना है कि एक समान फार्मूले के आधार पर ही हर देश की वैक्सीन की गुणवत्ता जांची जानी चाहिए। जी-20 की घोषणा पत्र के बाद भारत तेजी से दूसरे देशों के साथ हवाई मार्ग व पर्यटन को खोलने का समझौता कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दूसरा मुद्दा जिसकी भारत लगातार वकालत करता रहा है और जिसे घोषणा पत्र में मंजूरी दी गई है वह है पूरी दुनिया में बढ़ते उपभोक्तावाद को संतुलित करना। जी-20 की बैठक में भी भारत ने इसे शामिल करने पर खास जोर दिया। इसके बगैर पर्यावरण सुरक्षा की बात अधूरी है। इसी तरह से वर्ष 2014 सम्मेलन में पहली बार हिस्सा लेते हुए न्यूनतम कारपोरेट टैक्स की अवधारणा को लागू करने का प्रस्ताव किया था। शुरुआत में कई देशों ने इसका विरोध किया था लेकिन अब इस पर सहमति भी बनी है और रोम घोषणा पत्र में इसे शामिल भी किया गया है। भारत ने डाटा के इस्तेमाल को लेकर जो शंकाएं जताई थी, रोम घोषणा पत्र में उसका समाधान किया गया है। इसमें विकासशील देशों की आशंकाओं के समाधान की खास तौर पर ध्यान रखा गया है।

मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि डाटा का विश्वसनीय तरीके से इस्तेमाल होगा। ब्याज देनदारी को स्थगित करने के प्रस्ताव को मिली जगह इसी तरह से विकासशील देशों पर बकाये कर्ज पर ब्याज देनदारी को कुछ समय तक और स्थगित करने का प्रस्ताव भी जी-20 देशों ने स्वीकार किया है। पिछले वर्ष भारत के सुझाव पर ही इसे एक वर्ष के लिए टाला गया था। इससे दर्जनों को देशों को वित्तीय राहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पांच ग्रामीणों को अगवा किया

रायपुर, 7 नवम्बर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने पांच ग्रामीणों को अगवा कर लिया है। नक्सली शुक्रवार की शाम एक और शनिवार की शाम को चार ग्रामीणों को अपने साथ ले गए हैं। ग्रामीण जब रविवार शाम तक घर नहीं लौटे तब परिजनों ने पुलिस

- **नक्सली इन अपहृत ग्रामीणों की रिहाई के बदले अपने नक्सली साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।**

अधीक्षक से इसकी शिकायत की और ग्रामीणों की सकुशल वापसी की गुहार लगाई। सर्व आदिवासी समाज ने भी नक्सलियों से अपील की है कि वे सभी ग्रामीणों को छोड़ दें।

मिली जानकारी के मुताबिक जिन ग्रामीणों का अगवा किया है। वे सभी कोंटा थाना क्षेत्र के बंदा पंचायत स्थित बटेर गांव के निवासी हैं।